

GOVERNOR राज्यपाल

हमारे TOPIC EXPERT के साथ

देखें शाम 07:00 बजे



BY GS GURU





The Governor - State Executive

The Governor is the state's chief executive. He acts as a representative of the union government. The Governor has executive power over the state, and all executive actions must be made in his or her name. The constitution's Seventh Amendment, passed in 1956, allowed for the appointment of the same individual as Governor of two or more states.

राज्यपाल - राज्य कार्यपालिका

• राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के पास राज्य पर कार्यकारी शक्ति है, और सभी कार्यकारी कार्य उसके नाम पर किए जाने चाहिए। 1956 में पारित संविधान का सातवां संशोधन, दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की अनुमति देता है।





Constitutional Provisions

• The constitution states that the executive power of the state shall be vested in the Governor, who shall execute it either directly or through officers subordinate to him (Article 154).



संवैधानिक प्रावधान

• संविधान कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जो इसे सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित करेगा (अनुच्छेद 154)।





Constitutional Provisions

- There shall be a Council of Ministers, led by the Chief Minister, to assist and advise the Governor in the discharge of his functions, except when he is obliged by or under this Constitution to do all or any of them at his discretion. (Article 163).
- Part VI of the Constitution deals with the State Executive and includes Articles 153 to 167.

राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

- राज्यपाल को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि जब वह इस संविधान के तहत या इसके तहत अपने विवेक से सभी या कुछ करने के लिए बाध्य हो। (अनुच्छेद 163).
- संविधान का भाग VI राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 153 से 167 तक शामिल हैं।





Article	Provisions
153	Governors of state.
154	Executive power of state.
155 /	Appointment of Governor.
156	Term of office of Governor.
157	Qualifications for appointment as Governor.
158/	Conditions of Governor's office.
159	Oath and affirmation by the Governor.
160	Discharge of functions of the Governor certain contingencies.
161 🋂	Power of Governor to grant pardons and to suspend, remit or
X /	commute sentences in certain cases.
162	Extent of executive power of state.





The Governor - Appointment

- The Indian Constitution, in Article 165, enables and authorizes the President of India to appoint the Governor of State by warrant under his hand and seal for a five-year term.
- The Governor is not directly elected by the people, and neither is he elected indirectly by a special electoral college.

राज्यपाल - नियुक्ति

- भारतीय संविधान, अनुच्छेद 165 में, भारत के राष्ट्रपित को पांच साल की अविध के लिए अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने में सक्षम और अधिकृत करता है।
- राज्यपाल को सीधे लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है, और न ही वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।





The Governor - Appointment

- The Governor is appointed by the President and serves at his pleasure.
- The chief justice or the senior-most judge of the concerned High Court administers the Governor's oath of office (if the chief justice is unavailable).

राज्यपाल - नियुक्ति

- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अपनी मर्जी से कार्य करता है।
- मुख्य न्यायाधीश या संबंधित उच्च न्यायालय के विरष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं (यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपलब्ध है)।





The Governor - Appointment

- The Governor is appointed by the President and serves at his pleasure.
- The chief justice or the senior-most judge of the concerned High Court administers the Governor's oath of office (if the chief justice is unavailable).

राज्यपाल - नियुक्ति

- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अपनी मर्जी से कार्य करता है।
- मुख्य न्यायाधीश या संबंधित उच्च न्यायालय के विरष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं (यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपलब्ध है)।





The Governor - Qualifications



The Indian Constitution specifies two basic qualities for the selection of a Governor.

- He should be an Indian citizen.
- He must be at least 35 years old.

राज्यपाल - योग्यताएँ

भारतीय संविधान राज्यपाल के चयन के लिए दो बुनियादी गुण निर्दिष्ट करता है।

- वह भारतीय नागरिक होना चाहिए.
- उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए.





The Governor - Terms of Office

- The Governor serves for a term of five years from the date he assumed office, subject to the President's pleasure.
- Governors whose terms have expired may be reappointed in the same or a different state.
- The President has the authority to transfer a Governor from one state to another for the remainder of his tenure. Governor can serve over his five-year term until the next appointment is made.

राज्यपाल - कार्यालय की शर्तें

- राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन, राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है।
- जिन राज्यपालों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उन्हें उसी या अलग राज्य में पुनः नियुक्त किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति के पास राज्यपाल को उसके शेष कार्यकाल के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का अधिकार है। अगली नियुक्ति होने तक राज्यपाल अपने पांच साल के कार्यकाल तक सेवा दे सकते हैं।





Conditions of Office of Governor

- The Governor's office follows the procedures and conditions provided forth in the Indian Constitution.
 - ✓ He should not occupy any office of profit.
 - He should not be a member of the House of Parliament or any state legislature.

राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें

- राज्यपाल का कार्यालय भारतीय संविधान में दी गई प्रक्रियाओं और शर्तों का पालन करता है।
- उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए।
 - उसे संसद भवन या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।





Conditions of Office of Governor

- Parliament determines.
- During his tenure of office, his emoluments and allowances cannot be reduced.
- If he is appointed as Governor of two or more states, the Governor's allowances and emoluments are divided among the states in a proportion specified by the President.

राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें

- वह संसद द्वारा निर्धारित ऐसे भत्तों, परिलब्धियों और विशेषाधिकारों का हकदार है।
- उनके कार्यकाल के दौरान उनकी परिलिब्धियाँ और भत्ते कम नहीं किये जा सकते।
- यदि उसे दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल के भत्ते और परिलिब्धियाँ राष्ट्रपित द्वारा निर्दिष्ट अनुपात में राज्यों के बीच विभाजित की जाती हैं।





Removal

- A Governor of a state is an appointee of the President, according to Articles 155 and 156 of the Constitution, and he or she serves "at the pleasure of the President."
 - If a Governor continues to have the "pleasure of the President," he or she can serve another five years.

निष्कासन

- संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है, और वह "राष्ट्रपति की इच्छा पर" कार्य करता है।
- यदि राज्यपाल को "राष्ट्रपति की इच्छा" प्राप्त होती रहती है, तो वह अगले पाँच वर्षों तक सेवा कर सकता है।





Removal

- The grounds for a Governor's removal by the President are not specified in the constitution.
- The Governor's office has no fixed term and no security of tenure because the President can remove him at any time.
- After submitting his resignation letter to the President, the Governor can resign from his office.

निष्कासन

- राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाने का आधार संविधान में निर्दिष्ट नहीं है।
- राज्यपाल के कार्यालय का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता और कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं होती क्योंकि राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है।
- राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपने के बाद राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।





Constitutional Position

- Article 153 of the Indian Constitution mandates the appointment of a Governor in each state. The 7th Amendment to the Constitution however, allows for the appointment of the same person as Governor of two or more states.
- The provisions of Articles 154, 163, and 164 of the Constitution empower the constitutional post of Governor.

संवैधानिक स्थिति

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति का आदेश देता है। हालाँकि, संविधान का 7वां संशोधन एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की अनुमित देता है।
- संविधान के अनुच्छेद 154, 163 और 164 के प्रावधान राज्यपाल के संवैधानिक पद को सशक्त बनाते हैं।





Constitutional Position

- Article 154: The Governor shall have executive power over the state, which he shall exercise either directly or through officers subordinate to him in conformity with this Constitution.
- Article 163: There shall be a council of ministers, led by the Chief Minister, to assist and advise the Governor in the exercise of his powers, except when he is compelled to execute his functions at his discretion.

संवैधानिक स्थिति

- अनुच्छेद 154: राज्यपाल के पास राज्य पर कार्यकारी शक्ति होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुरूप सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
- अनुच्छेद 163: राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि जब वह अपने विवेक से अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए मजबूर हो।





Constitutional Position

Article 164: The council of ministers is collectively responsible to the state's legislative assembly. This provision is the cornerstone of the state's parliamentary system of governance.

संवैधानिक स्थिति

• अनुच्छेद 164: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। यह प्रावधान राज्य की संसदीय शासन प्रणाली की आधारशिला है।





The Governor - Power, and Functions

• The Governor has the same Executive, Legislative, Financial, and Judicial authorities as the President of India. However, the Governor's power is restricted in several ways compared to that of the President, as the Governor lacks the President's military, diplomatic, and emergency authorities.

राज्यपाल - शक्ति और कार्य

• राज्यपाल के पास भारत के राष्ट्रपित के समान ही कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक प्राधिकरण हैं। हालाँकि, राष्ट्रपित की तुलना में राज्यपाल की शक्ति कई मायनों में प्रतिबंधित है, क्योंकि राज्यपाल के पास राष्ट्रपित के सैन्य, राजनियक और आपातकालीन प्राधिकरणों का अभाव है।





Executive Powers of the Governor

• The Governor is the chief executive of the state.



The Governor appoints the Chief Minister and other cabinet members. They serve at the pleasure of the Governor [Article 164].

He may create rules for the efficient execution of a state government's work and its distribution among the ministers. [Article 166(3)]

- राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी होता है।
- राज्यपाल राज्य सरकार की ओर से सभी कार्यकारी निर्णय लेता है [अनुच्छेद 166(1)]।
 राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट सदस्यों की नियुक्ति करता है। वे राज्यपाल की
- राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट सदस्यों की नियुक्ति करता है। वे राज्यपाल की इच्छा पर कार्य करते हैं [अनुच्छेद 164]।
- वह राज्य सरकार के कार्यों के कुशल निष्पादन और मंत्रियों के बीच इसके वितरण के लिए नियम बना सकता है। [अनुच्छेद 166(3)]





Executive Powers of the Governor

- He appoints the state's advocate general and determines his tenure and conditions of service.
- He has the authority to recommend to the President the declaration of a state of constitutional emergency.
 - He may request from the Chief Minister any information pertaining to the administration of the state's affairs, as well as legislative suggestions [Article 167].

- वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका कार्यकाल और सेवा की शर्तें निर्धारित करता है।
- उसके पास राष्ट्रपति को संवैधानिक आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने की सिफारिश करने का अधिकार है।
- वह मुख्यमंत्री से राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित किसी भी जानकारी के साथ-साथ विधायी सुझावों का अनुरोध कर सकता है [अनुच्छेद 167]।



es/ ek का महासंग्राम



Executive Powers of the Governor

• The governor appoints the state election commissioner and establishes his term of office and working conditions [Article 243K].

He appoints the chairman of the state public service commission as well as the members of the commission. They can, however, only be dismissed by the President and not by a Governor.

- राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसके कार्यकाल और कामकाजी परिस्थितियों की स्थापना करता है [अनुच्छेद 243K]।
- वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ-साथ आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। हालाँकि, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।





Executive Powers of the Governor

- He serves as Chancellor of the state's universities and appoints Vice Chancellors.
- The Governor appoints the Chief Minister, while the Governor appoints the other ministers on the advice of the Chief Ministers.

- वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है और कुलपतियों की नियुक्ति करता है।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।





Administration of Scheduled Areas

- The President has the authority to declare an area a Scheduled Area. The Governor of the state submits a report to the President on the administration of the state's Scheduled Areas.
- The Governor has the authority to decide whether a certain act of parliament or state legislature is applicable or not to Scheduled Areas, and if so, whether it should be applied with modifications.

अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन

- किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्य का राज्यपाल राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपता है।
- राज्यपाल के पास यह निर्णय लेने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधानमंडल का एक निश्चित अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू है या नहीं, और यदि हां, तो क्या इसे संशोधनों के साथ लागू किया जाना चाहिए।





State Administration During President's Rule or a State Emergency

- The President's rule in the state may be declared in accordance with two articles of the constitution.
- Article 356: Give the President the authority to issue a proclamation if he believes that a situation has developed in which the state government cannot function in conformity with the provisions of the Constitution.

राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल के दौरान राज्य प्रशासन

- संविधान के दो अनुच्छेदों के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है।
- अनुच्छेद 356: राष्ट्रपित को उद्घोषणा जारी करने का अधिकार दें यदि उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति विकसित हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर सकती है।





State Administration During President's Rule or a State Emergency

• Article 365: Whenever a state government fails to comply with or give effect to any instruction from the center, the President may declare that a situation has developed in which the state's administration cannot be carried on in line with the provisions of the Constitution.

राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल के दौरान राज्य प्रशासन

• अनुच्छेद 365: जब भी कोई राज्य सरकार केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपित घोषणा कर सकता है कि ऐसी स्थिति विकसित हो गई है जिसमें राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है।





State Administration During President's Rule or a State Emergency

Following the proclamation of President's Rule or State Emergency, the Governor administers the state on behalf of the President, with the assistance of the state's Chief Secretary or advisors selected by the President.

राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल के दौरान राज्य प्रशासन

• राष्ट्रपित शासन या राज्य आपातकाल की घोषणा के बाद, राज्यपाल राज्य के मुख्य सिचव या राष्ट्रपित द्वारा चुने गए सलाहकारों की सहायता से, राष्ट्रपित की ओर से राज्य का प्रशासन करता है।





Legislative Powers of the Governor

- The Governor has the authority to call or dissolve the state legislature based on the advice of the state's ministerial council, which is led by the state's Chief Minister.
- The Governor presents to the state legislature the reports of the State Finance Commission, the State Public Service Commission, and the Comptroller and Auditor General.

राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ

- राज्यपाल के पास राज्य की मंत्रिस्तरीय परिषद की सलाह के आधार पर राज्य विधानमंडल को बुलाने या भंग करने का अधिकार है, जिसका नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं।
- राज्यपाल राज्य विधानमंडल को राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।





Legislative Powers of the Governor

- The Governor has the authority to address the state legislature at the start of its first session, as well as the first session of each year.
- The Governor addresses both Houses of the state legislature in a joint session [Article 176]. She/he has the ability to deliver messages to any or both Houses [Article 175].

राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ

- राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के पहले सत्र की शुरुआत में, साथ ही प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करने का अधिकार है।
- राज्यपाल एक संयुक्त सत्र में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं [अनुच्छेद 176]। उसके पास किसी या दोनों सदनों को संदेश देने की क्षमता है [अनुच्छेद 175]।





Legislative Powers of the Governor

- In conjunction with the Election Commission, the Governor has the authority to rule on the disqualification of a member of the state legislature [Article 192].
- When the state legislature is not in session, the Governor has the authority to issue ordinances. The ordinances must be authorised by the legislature within six weeks of their adoption [Article 213]. The Governor has the authority to revoke the ordinance at any moment.

राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ

- चुनाव आयोग के साथ मिलकर, राज्यपाल को राज्य विधायिका के सदस्य की अयोग्यता पर शासन करने का अधिकार है [अनुच्छेद 192]।
- जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेशों को उनके गोद लेने के छह सप्ताह के भीतर विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए [अनुच्छेद 213]। राज्यपाल के पास किसी भी समय अध्यादेश को रद्द करने का अधिकार है।





Financial Power of the Governor

- No money measure may be tabled in the State Legislative Assembly without the Governor's prior approval.
 - Under the supervision of the Governor, the annual financial statement or state budgets are submitted before the state legislative assembly [Article 202].

राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ

- राज्यपाल की पूर्वानुमित के बिना कोई भी धन संबंधी उपाय राज्य विधान सभा में पेश नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल की देखरेख में, वार्षिक वित्तीय विवरण या राज्य बजट राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं [अनुच्छेद 202]।





Financial Power of the Governor

- The Governor is in charge of the State Contingency Fund. She/he is entitled to make advances from the state contingency fund to cover any unforeseen expenses (Article 267).
- The Governor appoints the state finance commission for a five-year term. In its function, the commission examines the financial circumstances of municipalities and Panchayats [Article 243(1)].

राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ

- राज्यपाल राज्य आकस्मिकता निधि के प्रभारी हैं। वह किसी भी अप्रत्याशित खर्च को कवर करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने का हकदार है (अनुच्छेद 267)।
- राज्यपाल पांच साल के कार्यकाल के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अपने कार्य में, आयोग नगर पालिकाओं और पंचायतों की वित्तीय परिस्थितियों की जांच करता है [अनुच्छेद 243(1)]।





Judicial Powers of the Governor — Pandoning Journal [6]

Article 161 grants the Governor the authority to give pardons, reprieves, respites, or remission of penalty, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted by the Courts of any offence against any legislation related to a matter to which the State's executive jurisdiction extends.

राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ

• अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या सजा में छूट देने या निलंबित करने, कम करने या सजा को कम करने का अधिकार देता है। कार्यकारी क्षेत्राधिकार का विस्तार होता है.





Judicial Powers of the Governor

- Governor cannot commute a death sentence.
- In consultation with the state high court, the Governor appoints, posts, and promotes District Judges.
- The President consults the Governor before appointing the chief justice and judges of the relevant state high court.

राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ

- राज्यपाल मृत्युदंड को कम नहीं कर सकते।
- राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति करता है।
- राष्ट्रपति संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले राज्यपाल से परामर्श करता है।





Pardoning Powers of Governor

• Governor has the authority to pardon, reprieve, respite, remit, postpone, or commute the punishment or sentence of any person convicted of any violation of state law.

राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ

• राज्यपाल के पास राज्य कानून के किसी भी उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने, माफ करने, स्थगित करने या कम करने का अधिकार है।





- Q.1 Who among the following can remove the governor of a state from office?
 - निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है?

- a) Legislative Assembly
- b) Parliament /
- c) President
- d) Supreme Court







Q.2 For removal of a Governor from office, the President seeks

advice from __:

किसी राज्यपाल को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति से सलाह लेता है:

- a) Council of Ministers
- b) Supreme Court
- c) Chief Minister of concerned State









- Q.3 The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the States are submitted to which among the following? राज्यों के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तृत की जाती है?
 - a) President
 - b) Parliament
 - c) Governor
 - d) Chief Minister-







Q.4 Who is the chief executive head of the state?

🗸 राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है?

- a) Chief Minister
- b) Governor
- c) President
- d) None of the above







Q.5 Which article of the Indian Constitution provides for a Governor?

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का प्रावधान करता है?

- a) Article 152
- b) Article 153
- c) Article 154
- d) Article 156 /

